

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 119/2015/उदयपुर.

मैसर्स आर. सी. कंस्ट्रक्शन, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बोकाड़िया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/10/2016

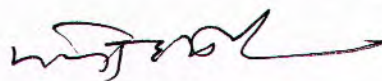
निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 64/वैट/14-15/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.11.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 07.01.2013 से आरोपित शास्ति अन्तर्गत धारा 58 रुपये 50,069/- के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिसे व्यवहारी ने इस अपील में विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2010-11 के लिये वैट अधिनियम की धारा 24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2013 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रुपये 50,069/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2014 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः आदेश पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध किया गया था। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 58 का विलोपन राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 दिनांक 9.3.2011 से कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण ही विधिविरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।
4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु आलौच्य अवधि के बहियात व बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु एकमात्र नोटिस दिनांक 07.12.2012 सुनवाई दिनांक 22.12.2012 के लिये जारी किया गया है। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 04.01.2013 को वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10ए एवं त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रथम उपलब्ध अवसर पर वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
7. बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करना एक चालू रहने वाला व्यतिक्रम है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन विलम्ब हेतु शास्ति आरोपण के जो प्रावधान प्रभावी हैं, उस प्रावधान के अनुसार शास्ति आरोपित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1986) 157 आई.टी.



लगातार.....3

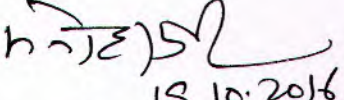
आर. 330 मायारानी पुंज में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे।

8. यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 के द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 को दिनांक 15.04.2011 से विलोपित कर दिया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु एकमात्र नोटिस दिनांक 07.12.2012 को जारी किया गया है एवं धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण आदेश दिनांक 07.01.2013 से किया गया है। अतः दिनांक 07.01.2013 को वेट अधिनियम की धारा 58 अस्तित्व में नहीं होने के कारण, धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना प्रथम दृष्टया ही विधिविरुद्ध हो जाता है।

9. उक्त विवेचन के मददेनजर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में त्रुटि की गयी है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2013 से वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

  
15.10.2016  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य